

दि कार्मिक पौर्णिमा

त्र्य : 7, अंक : 11

(प्रति दुधवार), इन्डौर, 3 नवंबर से 9 नवंबर 2021

पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

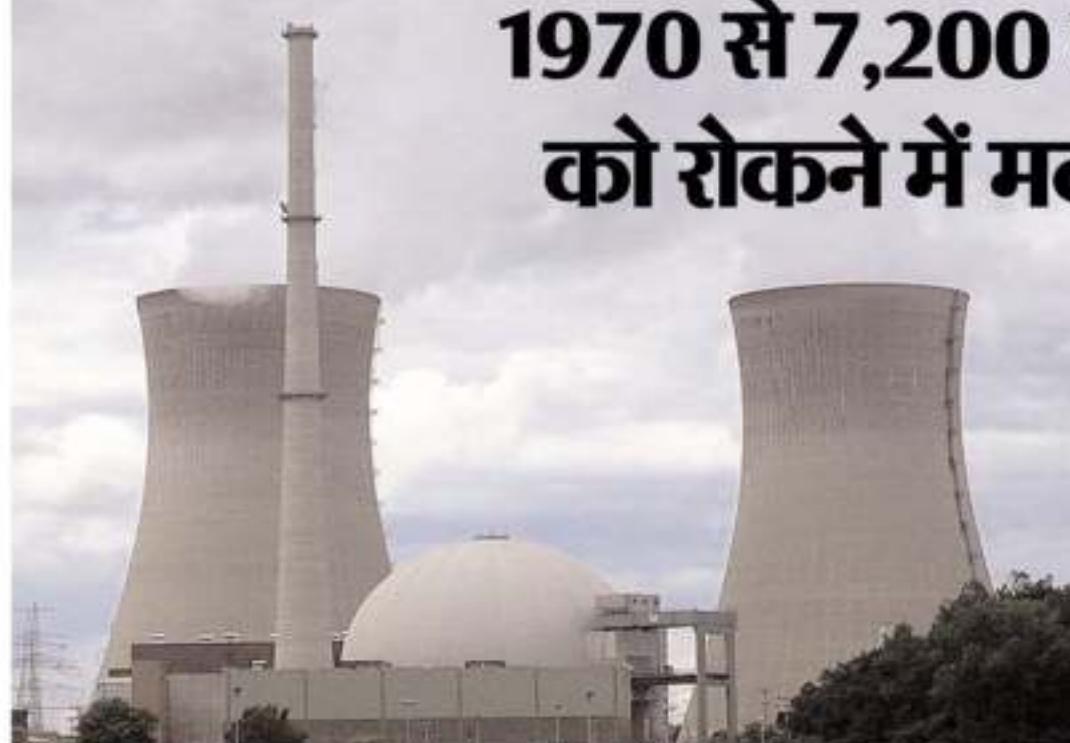
लक्ष्मी और कुबेर के लिए देव-दीवाली



कार्तिक मास में तीन दीवाली आती है। कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्दशी को छोटी दीवाली जिसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इसके बाद अमावस्या को बड़ी दीवाली मनाते हैं एवं पूर्णिमा को देव दीवाली मनाते हैं। उक्त तीनों ही दीवाली का बहुत ही खासा महत्व है।

आशाद् मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाते हैं तो वे चार माह बाद कार्तिक मास की एकादशी को उठते हैं। उनके उठने के बाद कार्तिक मास की पूर्णिमा को देव दीवाली मनाते हैं। यह दोवाली देवता मनाते हैं। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राचीन समय में इस तिथि पर शिवजी ने त्रिपुरासुर नाम के दैत्य का वध किया था। इसके अलावा मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर ही भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार भी लिया था। इसी दिन सिख गुरु नानकदेवजी का जन्म भी हुआ था। मान्यताओं के अनुसार देव दीपावली के दिन सभी देवता गंगा नदी के घाट पर आकर दीप जलाकर अपनी खुशी को बताते हैं। इस दिन यदि आप भी गंगा के तट पर दीप जलाकर देवताओं से किसी मनोकामना को लेकर प्रार्थना करेंगे तो वह निश्चित ही पूर्ण होगी। इस दिन घरों में तुलसी के पौधे के आगे दीपक जलाना और भगवान विष्णु की पूजा करने से लक्ष्मी सदा के लिए खुश हो जाती है। इस दिन यदि करेंगे एकमात्र ये उपाय तो लक्ष्मी और कुबेर आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। इस दिन दीपदान करने से लंबी आयु प्राप्त होती है। एक पते पर जलते हुए दीप रखकर नदी में छोड़े जाते हैं जिससे कर्ज और संकट से भी छुटकारा मिलता है।

1970 से 7,200 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मददगार रही परमाणु ऊर्जा



मुंबई। हाल ही में जारी एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि दुनिया भर में परमाणु रिएक्टरों ने कोयले की तुलना में 1970 के बाद से करीब 7,200 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मदद की है। गौरतलब है कि 2020 के अंत तक दुनिया भर में करीब 441 परमाणु रिएक्टर ऊर्जा पैदा कर रहे थे। इन परमाणु रिएक्टरों ने 2020 में कुल 2,553 टेरावाट-घंटे बिजली पैदा की थी, जोकि 2019 की तुलना में 104 टेरावाट-घंटे कम है।

यह रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फेडरेक्ट कन्वेशन (कॉप-26) से कुछ दिन पहले ही जारी की गई थी। गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन पर वार्ता के लिए यह सम्मेलन ग्लासगो में शुरू हो चुका है। इस बर्लिं न्यूक्लियर परफॉरमेंस रिपोर्ट 2021 के अनुसार कोविड-19 महामारी के चलते बिजली की मांग में कमी आ गई थी, जिससे जनरेटरों का उत्पादन कम हो गया था। रिपोर्ट के अनुसार जहां 2020 के दौरान अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप में बिजली के उत्पादन में गिरावट आई थी। एशिया में इसके उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई थी, हालांकि वो वृद्धि हाल के वर्षों की तुलना में बहुत कम थी। वहीं पूर्वी यूरोप, रूस और दक्षिण अमेरिका में कोई खास बदलाव नहीं रिकॉर्ड किया गया था। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 2020 के दौरान दुनिया भर में संचालित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की कुल बिजली उत्पादन क्षमता 392 गीगावाट थी। वहीं रिपोर्ट के

अनुसार 2020 के अंत तक कुल 441 रिएक्टर चालू अवस्था में थे। हालांकि अधिकांश वर्षों में कुछ रिएक्टर बिजली पैदा नहीं करते हैं। इस बारे में बर्लिं न्यूक्लियर एसोसिएशन के महानिदेशक सामा बिलबाओ वाई लियोन का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में स्थायी रूप से बंद किए गए आधे से अधिक रिएक्टर तकनीकी सीमाओं के कारण बंद नहीं थे, बल्कि उनके बंद होने की वजह उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए बनाई राजनीतिक नीतियां या फिर बाजार द्वारा परमाणु ऊर्जा के मूल्य को ठीक तरीके से न पहचानना थी। उनके अनुसार न्यूक्लियर एनजी, ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत है जो बहुत कम कार्बन उत्सर्जित करता है। देखा जाए तो यह कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का एक मीका है, जिसे दुनिया बर्बाद नहीं कर सकती। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में छह रिएक्टरों को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। इनमें फ्रांस के फेसेनहेम न्यूक्लियर पावर प्लाट के दो रिएक्टर शामिल हैं जिन्हें वहां की बिजली उत्पादन क्षमता में परमाणु हिस्सेदारी को कम करने के लिए बंद कर दिया गया था।

इसी तरह बाजार की स्थिति के चलते दो रिएक्टरों को बंद करना पड़ा था। वहीं स्वीडन में रिंगल 1 रखरखाव में कमी के कारण मार्च 2020 से ऑफलाइन हो गया था, जोकि जून में वापस चालू कर दिया गया था। इसी तरह रूस में लेनिनग्राद रिएक्टर को बदलाव के लिए बंद कर दिया गया था। 2020 में पांच रिएक्टरों को ग्रिड से जोड़ा गया था, जिनमें एक रिएक्टर बेलारूस और संयुक्त अरब अमीरात ने सम्मिलित रूप से लगाया था। हालांकि इन दोनों देशों में और भी इकाइयां निर्माणाधीन हैं। यदि भारत की बात करें तो देश में कुल 23 न्यूक्लियर रिएक्टर चालू अवस्था में हैं जबकि 7 अन्य के निर्माण का काम चल रहा है। इनकी कुल क्षमता 6,885 मेगावाट इलेक्ट्रिक है, जोकि कुल बिजली उत्पादन क्षमता का करीब 3.3 फीसदी हिस्सा है। वहीं जो रिएक्टर निर्माणाधीन है उनकी कुल क्षमता करीब 5,194 मेगावाट इलेक्ट्रिक है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के अनुसार परमाणु ऊर्जा जलवायु परिवर्तन से निपटने में मददगार रही है। उदाहरण के लिए, यह दुनिया की 10 फीसदी बिजली पैदा कर रही है। जो दुनिया की साफ-सुथरी ऊर्जा के करीब एक तिहाई हिस्से के बराबर है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा 2050 के लिए जारी नेट-जीरो रोडमैप का अनुमान है कि यदि दुनिया को नेट-जीरो महत्वाकांक्षा को पूरा करना है, तो उसे 2020 से 2050 के बीच परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को दोगुना करने की जरूरत पड़ेगी।



न्यूयार्क। नेट जीरो हासिल करने के लिए दुनिया भर के सभी क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को कम करने की आवश्यकता है। अब यूके के प्रमुख वैज्ञानिकों ने एक पेपर के माध्यम से नेट जीरो हासिल करने के लिए नए समाधान दुनिया के सामने रखे हैं। उन्होंने कहा है कि इन समाधानों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। साथ ही अगले दशक के लिए प्राथमिकता वाले शोध क्षेत्रों को भी इसके साथ जोड़ा जाना चाहिए, ताकि नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके।

अध्ययनकर्ताओं ने कहा इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रणालीगत बदलाव करने, जिसमें एक साथ काम करने वाली तकनीकें, सामाजिक और प्रकृति आधारित समाधानों के मिश्रण की आवश्यकता होगी। 2020 के दशक में शोध को उन क्षेत्रों के समाधान में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जिन्हें विशेष रूप से डीकार्बोनाइज करना मुश्किल है, जैसे विमानन, बिजली उत्पादन और भंडारण और समुद्री शिपिंग आदि। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में किए गए इस अध्ययन में नेट जीरो हासिल करने के समाधानों पर प्रकाश ढाला गया है। जिन्हें अब लागू किया जा सकता है, जैसे कि बैटरी से चलने वाले वाहनों का उपयोग, वर्तमान कार्बन उत्सर्जन करने वाले तरीकों से पैदा होने वाली बिजली के बजाय नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना, हाइड्रोजन का उपयोग आदि। साथ ही प्राथमिकता

के लिए भूमि उपयोग योजना में परिवर्तन, या भूमि का मिश्रित उपयोग, जीवाशम ईंधन से चलने वाले वाहनों का कम उपयोग आदि को शामिल किया जाना चाहिए। कॉप-26 यूनिवर्सिटी नेटवर्क द्वारा %2020 के दशक में नेट-जीरो सौल्यूशन एंड रिसर्च प्रायोरिटीज% नामक पेपर प्रकाशित किया गया है। इसमें यूके के 10 विश्वविद्यालयों के 26 प्रमुख वैज्ञानिक शामिल हैं। जिनमें कैम्ब्रिज के इंजीनियर डॉ. डैनियल ऐनालिस, प्रोफेसर डेविड सेबन, डॉ. शॉन फिट्जरलैंड शामिल हैं। डॉ. सैमुअल ग्रिमशॉ, डॉ. ह्रौग हंट, और डॉ. मारिया वेरा-मोरालेस। यह पेपर संयुक्त राष्ट्र कॉप-26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के शुरुआती दौर के महत्वपूर्ण समय पर प्रकाशित हुआ है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की सह-अध्ययनकर्ता डॉ. एरिक मैकी ने कहा कि हालिया आईपीसीसी रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने, उत्सर्जन को कम करने के लिए 2020 का दशक महत्वपूर्ण होगा। कॉप-26 में किए गए निर्णय इसे हासिल करने में महत्वपूर्ण होंगे। यह क्रॉस-डिसिप्लिनरी रिपोर्ट उन प्रमुख कार्यों की पहचान करके निर्णय लेने वालों की सहायता करेगी, जिन्हें हमें अभी लागू करना है। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जहाँ हमें अपने डीकार्बोनाइज करने के शोध प्रयासों पर तत्काल ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पेपर आठ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में नेट जीरो समाधान पर प्रकाश ढालता है, जो अभी से लागू की जाने वाली

कार्रवाइयों को निर्धारित करता है। उन्होंने कहा कि अगले दशक के लिए अनुसंधान प्राथमिकताएं इस तरह है - 1. बिजली (उत्पादन, भंडारण, प्रणाली और नेटवर्क), 2. इमारतों को बनाने में सुधार, 3. सड़क परिवहन 4. उद्योग, 5. भूमि/समुद्री उपयोग और कृषि, 6. विमानन और शिपिंग, 7. अपशिष्ट प्रबंधन, 8. ग्रीनहाउस गैस का निवारण (जीजीआर)। प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) - प्रमुख कार्रवाइयां जो सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान का समाधान करने के लिए प्रकृति के साथ काम कर सकती हैं। जबकि आर्थिक सुधार का समर्थन भी करती हैं जिस पर अलग से रोशनी डाली जा सकती है। कैम्ब्रिज के कैवेंडिश प्रयोगशाला में मैरी-व्यूरी रिसर्च फैलो, सह-अध्ययनकर्ता डॉ. एलिजाबेथ टेनीसन ने कहा कि आने वाला दशक कार्रवाई और कार्यान्वयन के लिए होगा। हमें उन समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है जिन्हें व्यावहारिक रूप से 2030 से पहले लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए इनमें से कुछ समाधानों पर प्रकाश ढालती है। कोई अकेला क्षेत्र इसका समाधान नहीं कर सकता है। नेट जीरो हासिल करने के लिए कई क्षेत्रों में एक साथ काम करने की आवश्यकता है। हमें उम्मीद है कि यह नीति न केवल बदलाव को प्रभावित करेगा बल्कि आगे के नवाचारों को भी प्रोत्साहित करेगा। रिपोर्ट में सुझाए गए

कॉप-26-नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिकों ने दिए सुझाव

अतिरिक्त समाधानों में इमारतों की रेट्रोफिटिंग, कम कार्बन कृषि प्रथाओं को बाजार में लाने के लिए आर एंड डी निवेश में वृद्धि, करना, पहले कम कार्बन का समर्थन करने के लिए 2020 के मध्य तक कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज (सीसीयूएस) शामिल करना आदि। अध्ययनकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि प्रत्येक समाधान का मूल्यांकन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, ऊर्जा दक्षता और सामाजिक प्रभावों के संबंध में किया जाना चाहिए। ताकि लंबे समय में नीतियों को विकसित करने, निवेश और अनुसंधान प्रयासों के सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने, उद्योग निवेशों को सुरक्षित और जिम्मेदार मार्गदर्शन करने के लिए आधार प्रदान किया जा सके। कैम्ब्रिज के इंजीनियरिंग विभाग के सह-अध्ययनकर्ता प्रोफेसर डेविड सेबन ने कहा कि विश्वविद्यालयों के इस समूह को अपनी विशेषज्ञता को बढ़ाते हुए और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुकाबले में शोध और तत्काल कार्रवाई की जरूरतों के बारे में व्यापक आम सहमति बनाना महत्वपूर्ण है। अध्ययनकर्ता ने बताया कि कॉप-26 यूनिवर्सिटी नेटवर्क का उद्देश्य महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन परिणामों को वितरित करने के लिए एक साथ काम करना है। साथ ही गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन कॉप-26 के लिए साक्ष्य और शैक्षणिक विशेषज्ञता तक पहुंच में सुधार करना शामिल है।

दीपाली के पांच दिनी उत्सव के शुभ मुहूर्त

नरक चतुर्दशी (3 नवंबर) के शुभ मुहूर्त

तीन नवंबर के दिन ब्रह्मोदयी तिथि सुबह 09 बजकर 02 मिनट तक रहेगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होकर 4 नवंबर सुबह 06 बजकर 03 मिनट तक रहेगी। इसलिए अधर्यग स्नान समय 4 नवंबर प्रातः 06.06 से 06.34 तक रहेगा। योग-सर्वार्थ सिद्धि योग। श्रवण मुहूर्त 05.02 से 05.50 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 01.33 से 02.17 तक। गोधूलि मुहूर्त शाम 05.04 से 05.28 तक। संध्या मुहूर्त शाम 05.15 से 06.32 तक। अमृत काल मुहूर्त रात्रि 09.16 से 10.42 तक। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6.10 से रात 08.06 तक। महानिशीष काल मुहूर्त रात्रि 11.38 से 12.30 तक।

दिन का चौथांशीया- लाभ सुबह 06.38 से 08.00 तक। अमृत प्रातः 08.00 से 09.21 तक, शुभ, प्रातः 10.43 से 12.04 तक, लाभ शाम 04.08 से 05.30 तक।

रात का चौथांशीया- शुभ शाम 07.09 से 08.47 तक। अमृत 08.47 से 10.26 तक। लाभ 03.22 से

05.00 तक।

दीपाली (4 नवंबर) के शुभ मुहूर्त

प्रीत योग सुबह 11.10 तक। उसके बाद आयुष्मान योग पूरे दिन-रात रहेगा। अभिजीत मुहूर्त प्रातः 11.42 से दोपहर 12.26 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 01.33 से 02.17 तक। गोधूलि मुहूर्त शाम 05.04 से 05.28 तक। संध्या मुहूर्त शाम 05.15 से 06.32 तक। अमृत काल मुहूर्त रात्रि 09.16 से 10.42 तक। प्रदोष काल मुहूर्त शाम 6.10 से रात 08.06 तक। महानिशीष काल मुहूर्त रात्रि 11.38 से 12.30 तक।

दिन का चौथांशीया- शुभ प्रातः 06.39 से 08.00 तक, लाभ दोपहर 12.04 से 01.25 तक, अमृत दोपहर 01.25 से 02.47 तक, शुभ शाम 04.08 से 05.29 तक।

रात का चौथांशीया- अमृत शाम 05.29 से 07.08 तक, लाभ 12.04 से 01.43 तक। शुभ रात्रि

03.22 से 05.01 तक।

गोवर्धन पूजा (5 नवंबर) के शुभ मुहूर्त

शुब्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि 5 नवंबर को सुबह 02.44 से रात्रि 11.14 तक रहेगी। इस दिन आयुष्मान योग, शोभन योग और सौभाग्य योग रहेगा।

पूजा के मुहूर्त- सुबह 06.35 से 08.47 तक और साथेंकाल 03.21 से 05.33 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.42 से दोपहर 12.26 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 01.32 से 02.17 तक, अमृत काल मुहूर्त दोपहर 02.26 से 03.51 तक। गोधूलि मुहूर्त शाम 05.03 से 05.27 तक। संध्या मुहूर्त शाम 05.14 से 06.32 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11.16 से 12.08 तक।

दिन का चौथांशीया- शुभ प्रातः 08.02 से 09.22 तक। लाभ दोपहर 1.25 से 2.46 तक। अमृत 2.46 से 4.07 तक।

रात का चौथांशीया- लाभ 8.47 से 10.26 तक, शुभ रात्रि 00.05 से 01.44 तक, अमृत रात्रि 01.44 से 03.23 तक।

भाई दूज (6 नवंबर) के शुभ मुहूर्त

भाई दूज तिलक का शुभ समय- दोपहर 01.10 से 03.21 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11.19 से दोपहर 12.04 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 01.32 से 02.17 तक, अमृत काल मुहूर्त दोपहर 02.26 से 03.51 तक। गोधूलि मुहूर्त शाम 05.03 से 05.27 तक। संध्या मुहूर्त शाम 05.14 से 06.32 तक, निशिता मुहूर्त रात्रि 11.16 से 12.08 तक।

दिन का चौथांशीया- शुभ प्रातः 08.02 से 09.22 तक। लाभ दोपहर 1.25 से 2.46 तक। अमृत 2.46 से 4.07 तक।

रात का चौथांशीया- लाभ शाम 05.28 से शुभ-रात्रि 8.46, अमृत रात्रि 10.25 से।



वास्तु के हिसाब खरीदें और दीपक जलाएं

आपका घर या मकान किस दिशा में है और उसका मुख्य द्वार किस दिशा में है वह जानकर आप बया खरीदें और द्वार पर कौन-सा दीपक जलाएं, इसके लिए वास्तु टिप्पणी जरूरी हैं, जिससे आपका धनतेरस पर लाभ मिल सकता है। यदि आपके घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में है तो आप चांदी का सामान जरूर खरीदें। क्षमता है तो हीरा भी खरीद सकते हैं और फिर द्वार पर दीपक जलाएं, तो उसमें कौड़ी जरूर डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में है तो सोने या तांबे से बना सामान खरीदें। मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो उसमें राई अवश्य डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार नेत्रघन्य दिशा में है तो चांदी या तांबे से बनी वस्तु खरीदें और द्वार पर दीपक जलाएं तो उसमें लौंग जरूर डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं तो उनमें एक किशमिश जरूर डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार इशान दिशा में है तो चांदी या मोती खरीदें और दीपक में खोदी मिश्री जरूर डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा में है तो सोना या तांबा खरीदना चाहिए और द्वार पर दीपक जलाएं तो उनमें धोड़ा कुमकुम जरूर डालें। यदि आपके घर का मुख्य द्वार पर यूवा दिशा में है तो आपको सोना या तांबा खरीदना चाहिए और द्वार पर दीपक जलाएं तो उनमें धोड़ा कुमकुम जरूर डालें। इसके अलावा इस दिन नवीन झाड़ू एवं सूरज़ा खरीदकर उनका पूजन करें। वयाशालि तांबे, पीतल, चांदी के गृह-उपयोगी नवीन वर्तन व आभूषण क्रय करें। शुभ मुहूर्त में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में नई गाड़ी बिछाएं अथवा पुरानी गाड़ी को ही सफ कर फिर स्थापित करें।

पर्यावरण के क्षेत्र में बड़ी ताकत बन कर उभर रहा है चीन

शिंघाई। ऐसे समय में, जब हम जिंटगी को ऑनलाइन और ऑफलाइन के पैमानों पर देखने को नज़र रहे हैं, हम एक ऐसी वैश्विक दुनिया का सामना कर रहे हैं, जैसी वह पहले कभी नहीं थी। दिल्ली ने एक कम्प्यूटर बेचने वाले से बातचीत में एक खरीदार को इसका एहसास तब हुआ, जब चीन से आपूर्ति में देटी के चलते वह अपनी पसंद का लैपटॉप नहीं खरीद सका। बाद ने एक सिगरेट बेचने वाले से बात करने पर उसने पाया कि देश में गैस वाले लाइटरों की भी कमी हो गई है।

इसकी बजह यह थी कि देश ऐसे लाइटरों का आयात ही कम कर रहा है, जिसके चलते स्थानीय दुकानदारों के पास इनकी मांग बढ़ रही थी। कम्प्यूटर बेचने वाले की भाषा में ही कहें तो, अब ऐसा कुछ नहीं है, जिसे देसी कहा जाए और ऐसा कोई सामान नहीं है, जो चीन की मदद के बिना बन सके। चीन इस दौर और हम सबके जीवन की नई धूरी है। नए वैश्विक बदलावों पर गैर करें तो दुनिया एक बार फिर से दो-ध्रुवीय हो रही है। पिछली बार की तरह इस बार अमेरिका और सोवियत संघ, दो ध्रुव नहीं हैं बल्कि इस बार का विभाजन चीन और बाकी सारी दुनिया है, खासकर चीन बनाम वे देश जो विश्व के भू-राजनीतिक परिदृश्य में दबदबा रखते हैं। बाकी बचे देश बाद में अपनी स्थिति के मुताबिक इस दो-ध्रुवीय हो रही वैश्विक संरचना में अपना पक्ष चुन सकते हैं। यह नया ध्रुवीकरण साफतौर पर पर्यावरण को अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करने की गलत नीतियों का परिणाम है, जिसमें कम से कम नुकसान उठाकर ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने पर जोर दिया जाता है। चीन ने वैश्विक ताकत बनने की अपनी इच्छा को कभी नहीं छिपाया। हालांकि उसका गस्ता बाकी दुनिया द्वारा दिखाए गए आर्थिक मॉडल ने ही तय किया। अमीर देशों ने वैश्विक दुनिया में उपनिवेशी व्यापार की खातिर चीन को सामानों की सस्ती फैक्ट्री बनाने की नीति बनाई थी। वे चाहते थे कि वे खुद को पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाते हुए नीतिकता दर्शाते रहें।

बल्कि साफ-साफ कहें तो उनकी मंशा अपना उत्सर्जन और प्रदूषण चीन को आयात कर खुद को पर्यावरण के पैमानों पर खरा दिखाए रखने की थी। इसका नतीजा यह रहा कि चीन ने इसके बदले में अपने सामरिक शास्त्रागार तैयार की रणनीति बनाई। उसने बाकी सारी दुनिया को अपने पर इस कदर निर्भर बना लिया कि आज अगर उसका जहाज आने में कुछ दिनों की देरी हो जाती है तो भारत में गैस वाले लाइटरों की कमी होने लगती है। यानी निर्विवाद रूप से वह द्वि-ध्रुवीय दुनिया का ऐसा संतं बन चुका है, जिसका बाकी दुनिया को या तो जबाब देना है या फिर जिसके साथ संतुलन बिठाना है। उसकी जड़ें विश्व अर्थव्यवस्था में इतनी मजबूत हो चुकी हैं और उसका विवरण है कि कोई भी देश वर्तमान में उसे केंद्र में रखे बगैर दुनिया की कल्पना नहीं कर सकता। दूसरी ओर जलवायु संकट जैसे पर्यावरण के मुद्दों पर भी दुनिया दो-ध्रुवीय हो रही है, जिसने विकसित देशों को गुनाहगार और विकासशील देशों को भूक्षेषणी के तौर पर आमने-सामने खड़ा कर दिया है। ऐतिहासिक रूप से इस तथ्य के बावजूद कि विकसित देश पहले कॉर्बन के बड़े उत्सर्जक रहे हैं, चीन अब सबसे ज्यादा कॉर्बन उत्सर्जन करने वाला देश है। ऐसे कई वैश्विक सम्मेलन हो चुके हैं, जिनमें समुद्र से लेकर भूमि तक जैव-विविधता के मुद्दे शामिल रहे हैं लेकिन अब ऐसे हर सम्मेलन में चीन सहित विकसित और विकासशील देशों के बीच ध्रुवीकरण होता है। हाल ही में चीन ने धरती के स्वास्थ्य और इसके लिए अपनी जिम्मेदारी लेने के बारे में बात करना शुरू किया है। वह 2060 तक खुद को शून्य-कॉर्बन वाला देश बनाना चाहता है। आर्थिक क्षेत्रों की तरह, चीन पर्यावरणीय संबंधी मामलों में भी एक ताकत के रूप में उभर रहा

प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से किए पांच बादे

नई दिल्ली। कॉप-26 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो- पीआईबी कॉप-26 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फोटो- पीआईबी कॉप-26 के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फेमवर्क सम्मेलन (कॉप 26) को संबोधित करते हुए भारत की ओर से पांच बादे किए। उन्होंने कहा, + क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच, मैं भारत की ओर से, इस चुनौती से निपटने के लिए पांच अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगत देना चाहता हूं। पहला- भारत, 2030 तक अपनी गैर जीवाशम ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा- भारत, 2030 तक अपनी 50 प्रतिशत ऊर्जा की जरूरत अक्षय ऊर्जा से पूरी करेगा। तीसरा- भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल अनुमानित कार्बन उत्पर्जन में एक बिलियन (अरब) टन की कमी करेगा। चौथा- 2030 तक भारत, अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता (इन्टेसिटी) को 45 प्रतिशत से भी कम करेगा। और पांचवा- वर्ष 2070 तक भारत, नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा, +मैं आज आपके सामने एक, बन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। यह बन-वर्ड एक शब्द, क्लाइमेट के संदर्भ में, बन वर्ल्ड-एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व की आबादी का 17 प्रतिशत होने के बावजूद, भारत केवल पांच प्रतिशत कार्बन उत्पर्जन के लिए जिम्मेवार है। बावजूद इसके भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कार कसर बाकी नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा कि यह सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए बायदे, खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी जलवायु कार्रवाई (क्लाइमेट एक्शन) पर अपनी आकांक्षा बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व की आकांक्षा वही नहीं रह सकते जो पेरिस समझौते के समय थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि चूंकि सबसे अधिक कार्बन उत्पर्जन विकसित देश करते हैं, इसलिए उन्हें हर हाल में क्लाइमेट फाइनेंस के अपने

बादों को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह कार्बन उत्पर्जन को मॉनीटर किया जाता है, ठीक उसी तरह अब क्लाइमेट फाइनेंस को मॉनीटर किया जाएगा, ताकि विकसित देशों पर दबाव बनाया जा सके। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने % एक्शन एंड सॉलिडेटी-द क्रिटिकल डिकेंड कार्यक्रम में कहा कि वैश्विक जलवायु वार्ता में अनुकूलन (एडशन) को उतना महत्व नहीं मिला है जितना न्यूनीकरण (मिटिगेशन) को। यह उन विकासशील देशों के साथ अन्याय है, जो जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि भारत समेत अधिकतर विकासशील देशों के किसानों के लिए जलवायु बड़ी चुनौती है - फसल चक्र में बदलाव आ रहा है, बेसमय बारिश और बाढ़, या लगातार आ रहे तूफानों से फसलें तबाह हो रही हैं। पैदल के स्तर से ले कर सस्ते धरां तक, सभी को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ सक्षम बनाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, +इस संदर्भ में मेरे तीन विचार हैं। पहला, एडाप्टेशन को हमें अपनी विकास नीतियों और परियोजनाओं का मुख्य अंग बनाना होगा। भारत में नल से जल, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला, क्लीन कूकिंग फ्यूल फॉर ऑल जैसी परियोजनाओं से हमारे जरूरतमंद नागरिकों को एडाप्टेशन बेनेफिट्स तो मिले ही हैं, उनकी क्लालिटी ऑफ लाइफ भी सुधरी है। दूसरा, कई ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने का ज्ञान है। हमारी एडाप्टेशन नीतियों में इन पारंपरिक अनुभूतों को उचित महत्व मिलना चाहिए। ज्ञान का ये प्रवाह, नई पीढ़ी तक भी जाए, इसके लिए स्कूल के सैलेबस में भी इसे जोड़ा जाना चाहिए। लोकल कंडीशन के अनुरूप लाइफस्टाइल का संरक्षण भी एडाप्टेशन का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हो सकता है। तीसरा, एडाप्टेशन के तरीके चाहे लोकल हों, किन्तु पिछड़े देशों को इनके लिए ग्लोबल सोर्ट मिलना चाहिए।

2040 तक सूखे की चपेट में होगी दुनिया की एक तिहाई कृषि भूमि

नई दिल्ली। हाल ही में चैथम हाउस द्वारा जारी रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज रिस्क एसेसमेंट 2021 से पता चला है कि यदि वैश्विक उत्पर्जन में हो रही वृद्धि इसी तरह जारी रहती है तो 2040 तक दुनिया की करीब एक तिहाई कृषि भूमि सूखे की चपेट में होगी। यहीं नहीं रिपोर्ट के भविष्य में यह समस्या और गंभीर रूप से सकती है क्योंकि जिस तरह से वैश्विक आबादी में वृद्धि हो रही है उसके चलते 2050 तक भोजन की कमी को पूरा करने के लिए 50 फीसदी अधिक पैदावार करने की आवश्यकता होगी।

गौरतलब है कि जलवायु परिवर्तन से जुड़े जटिल खतरों को उजागर करने वाली यह रिपोर्ट ग्लासगो में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कॉप-26) के कुछ दिन पहले ही जारी की गई है। इस बारे में शोधकर्ताओं ने जानकारी दी है कि यदि दुनिया के सबसे बड़े उत्पर्जन के देश अपने उत्पर्जन को कम करने में विफल रहते हैं तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अनुमान है कि 2040 तक स्थिति इतनी गंभीर हो जाएगी कि तब देश चाहकर भी जलवायु परिवर्तन के असर से बचने के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने दुनिया की तीन सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलों में से मक्का का उदाहरण देते हुए जानकारी दी है कि अमेरिका, चीन, ब्राजील और अर्जेटीना दुनिया का करीब 87 फीसदी मक्का पैदा करते हैं। उनका अनुमान है कि 2040 तक यह देश इसके उत्पादन में आने वाली भारी गिरावट का सामना कर सकते हैं। वर्तमान में देशों तो इन देशों में इसकी पैदावार में आने वाली गिरावट की सम्भावना (10 फीसदी या उससे ज्यादा) बिलकुल न के बराबर है। लेकिन 2040 तक यह हर साल लगभग 6.1 फीसदी की दर से बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक एक साथ कई क्षेत्रों में फसलों के विफल होने की सम्भावना करीब 50 फीसदी तक बढ़ जाएगी। अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर 2040 तक गंभीर सूखे से प्रभावित कृषि भूमि के सालाना 32 फीसदी तक बढ़ने की सम्भावना है, जोकि ऐतिहासिक औसत से तीन गुना अधिक है। यह भी अनुमान है कि दुनिया भर में कई प्रमुख कृषि उत्पादक क्षेत्र 2050 तक कृषि अवधि में कम से कम 10 दिनों की कमी का सामना करने को मजबूर हो जाएगी। यह कमी सर्वियों में उगाए जाने वाले गेहूं के लिए 60 फीसदी, बसंत में पैदा किए जाने वाले गेहूं के लिए 40 फीसदी और चावल के लिए 30 फीसदी तक बढ़ सकती है। यहीं नहीं रिपोर्ट के अनुसार 2040 तक हर साल 70 करोड़ लोग गंभीर सूखे का सामना करने को मजबूर होंगे। वहीं सूखा की यह स्थिति साल के छह महीनों तक बनी रहेगी। यहीं नहीं रिपोर्ट के मुताबिक भविष्य में उत्तरी अफ्रीका, पश्चिम एशिया, पश्चिमी और मध्य यूरोप और मध्य अमेरिका की 10 फीसदी से ज्यादा आबादी लम्बी अवधि तक चलने वाले गंभीर सूखे से प्रभावित रहेगी। वहीं पूर्वी और दक्षिण एशिया के बाद अफ्रीका में सबसे ज्यादा लोग इस गंभीर सूखे का सामना करने को मजबूर हो जाएंगे, 2050 तक जिनकी संख्या करीब 18 करोड़ होंगी। ऐसे में रिपोर्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा उत्पर्जन करने वाले देशों से यह आग्रह किया गया है कि वो कॉप-26 सम्मलेन में राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के महत्वाकांशी संशोधनों के माध्यम से उत्पर्जन में कमी लाने का प्रयास करें। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करने से निम्न-कार्बन प्रौद्योगिकियों में बढ़े पैमाने पर तेजी से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।